जहाजरानी में विस्तार

+

*४४. { श्री पहाड़िया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बालकृष्ण वास्निक :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड के सभापति ने सुझाव दिया है कि हाल ही में अमरीका के साथ हुए खाद्य करार से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये हमारी जहाजरानी का विस्तार किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) इस विषय पर अभी विचार किया जा रहा है ।

श्री पहाड़िया : मैं यह जानना चाहता हूं कि अमरीका से जो यह अनाज आयेगा वह किस अनुपात में भारतीय जहाजों में आयेगा और कितने अनुपात में दूसरे देशों के जहाजों में आयेगा और उन विदेशी जहाजों को हमें कितना किराया देना पड़ेगा ?

श्री राज बहादुर : जो मुआहिदा हुआ है उस के अनुसार ५० प्रतिशतः अनाज अमरीकी जहाजों में आयगा और बाकी पचास प्रतिशतः के लिये हमारा अधिकार है कि उसको हम अपने जहाजों में लायें या जो दूसरे जहाज हम इसके वास्ते चार्टर कर सकें उन पर लायें । अब आज जो दरें हैं और भाव है और जो इनका फ्रेट रेट है वह लगभग ३ पौंड प्रति टन है और उसके हिसाब से करीब ७०-८० करोड़ रुपया अनाज को लाने में बतौर भाड़े के लगेगा ।

Shri Damani: May I know whether it is a fact that at present the prices of ships have gone down considerably and there are many ships available for ready delivery? If so, may I know whether Government is contemplating to purchase some ships to bring these foodgrains or to allow private companies to purchase some ships for saving foreign exchange?

Shri Raj Bahadur: It is true that these days it is a buyer's market so far as the purchase of ships is concerned and ships are definitely available at low prices comparatively speaking. But the question is how far can we spare to buy ships and that matter is exactly under examination now.

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो पचास सैकड़ा आपके अधीन होगा तो इस पचास सैकड़े में हिन्दुस्तानी कम्पनियों का शेयर क्या होगा और साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ८० करोड़ रुपया आप इसमें बतौर भाड़ा देने के वास्ते जा रहे हैं तो क्या यह उचित नहीं होगा कि ४० करोड़ रुपया लगा कर आप अपने जहाज ले लें ?

श्री राज बहादुर : जहां तक हिस्से का सम्बन्ध है जैसे मैंने कहा इस पचास प्रतिशतः पर हमारा अधिकार है । शिपर्स च्वाएस है और गवर्नमेंट की च्वाएस होगी कि वह जिसका भी जहाज लाना चाहे लाये और जाहिर है कि गवर्नमेंट अपने देश के जहाज लाना पसन्द करेगी । अब प्रश्न तो है कि क्या हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जहाज उपलब्ध हैं और क्या ७०-८० करोड़ रुपया इस काम के वास्ते हमारे पास एकदम तैयार है, ३०-४० करोड़ रुपये हों तो शायद यह काम किया जा सकता है । अब वह कितना मिल सकता है और कितना आ सकता है यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका कि उत्तर मैं इस समय नहीं दे सकता ।

श्री रघुनाथ सिंह : ८० करोड़ रुपया जब हम बतौर भाड़े के देने पड़ते हैं तो इस ८० करोड़ में से ४० करोड़ पर लेकर क्यों न हम अपने जहाज खरीद लें ?

श्री राज बहादुर : आधा भाड़ा तो हमें अपने एग्रीमेंट के मुताबिक देना नहीं होगा, बाकी आधा देना होगा

श्री रघुनाथ सिंह : इसलिये मैंने ४० करोड़ कहा है ।

श्री राज बहादुर : जी हां, इसलिये तो मैं कह रहा हूं कि इस ४० करोड़ में से कितना मिल सकता है, कितने जहाज ले सकते हैं यह सारा प्रश्न विचाराधीन है ।

Shrimati Renu Chakravartty: I wanted to know whether the rates which are being quoted by the American shippers are much higher than those average rates quoted by other shippers; and, if so, how much.

Shri Raj Bahadur: I think the Food Minister have already given out that they would like to go by the world freight rates in this behalf and that is the rate that I just now quoted, that is, about £3 per ton, at the moment. This is, of course, a fluctuating rate; it may go up or go down.

Shri Hem Barua: May I know whether it is a fact that only 6 to 7 per cent of the cargo of 17 million tons of foodgrains from U.S.A. is proposed to be lifted by Indian shipping? If so, after Indian shipping is expanded as is proposed to be done, what percentage this proposed expansion is likely to cover?

Shri Raj Bahadur: We have not fixed or even calculated what percentage the Indian shipping will be able to lift out of the entire cargo. That would depend upon the number of ships available to us and that is a point on which I cannot give a specific answer unless I know how much financial resources we can mobilise for the purpose.

Shri Hem Barua: If I am not mistaken, the Food and Agriculture Minister made a statement like this that 50 per cent would be lifted by American ships and out of the other 50, 6 to 7 per cent is likely to be lifted by Indian shipping and the rest by other ships; and in that context I put this question.

The Minister of Food and Agriculture (Shri S. K. Patil): I never made a statement like that. The fact is that under the American law 50 per cent has to be carried by the American bottoms and the remaining 50 per cent is entirely at our disposal. It depends upon our capacity to bring it. Six to seven per cent is the average that I have been seeing for the last 2 or 3 years. That is the average we bring. That does not prevent us to increase that percentage.

श्री पहाड़िया : मैं यह जानना चाहता हूं कि ४० करोड़ रुपये के लगभग उस पर खर्च होगा तो जब इसके लिये कोई समय निश्चित नहीं है कि बहुत जल्दी ही हमें सारा अनाज मंगा लेना है तो क्यों न उस रुपये को एक साथ खर्च करने के धीरे धीरे खर्च करें ?

Mr. Speaker: The same thing was asked by Shri Raghunath Singh.

Short Supply of Wagons

\+

*47. { **Shri T. B. Vittal Rao:**
{ **Shri Rami Reddy:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the reasons for the short supply of covered wagons for the transport of rice from Andhra region to Kerala *via* Vijayawada and Madras during the month of April, 1960;

(b) the number of wagons required and the number actually allotted during that month; and